www.deshkiupasana.com
राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र
RNI NO - UPHIN/2022/86937
जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE
सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 अंक – 324 जौनपुर बुधवार, 15 जुलाई 2026 सान्ध्य दैनिक (संस्करण) पेज – 4 मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

11 दिन में 2.75 लाख के पार पहुंचे अमरनाथ श्रद्धालु

श्रीनगर, (एजेंसी)। 3 जुलाई से कश्मीर में चल रही श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 में अब तक 2.75 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। मंगलवार को 5,335 यात्रियों का एक और जत्था जम्मू से घाटी के लिए रवाना हुआ। अधिकारियों ने बताया कि पिछले 11 दिनों में लगभग तीन लाख यात्रियों ने यात्रा पूरी की है। सोमवार को 24,259 यात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए और 5,335 तीर्थयात्रियों का एक और जत्था जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से दो सुरक्षा–प्राप्त काफिलों में घाटी के लिए रवाना हुआ। इनमें से 3,599 यात्री नुनवान (पहलगाम) बेस कैंप जा रहे हैं, जबकि 1,736 यात्री बालटाल बेस कैंप जा रहे हैं। इससे पहले सोमवार को जम्मू–श्रीनगर नेशनल हाईवे पर रामबन जिले के चंदरकोट के पास एक दुर्घटना में 18 तीर्थयात्री घायल हो गए। इस दुर्घटना में एक बस का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि किसी भी तीर्थयात्री को गंभीर चोटें नहीं आईं। इस टक्कर में तीन गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। अधिकारियों के अनुसार, यह हादसा सुबह करीब 7:20 बजे हुआ, जब पहलगाम जा रहे काफिले की आखिरी गाड़ी (जेके01वाई–1044) बस के ब्रेक चंदरकोट लंगर स्थल के पास फेल हो गए। बस काफिले की ही एक दूसरी बस (जेके01वाई–1052) से टकरा गई और वहां खड़ी एक कार (जेके 21 के–8115) को भी नुकसान पहुंचाया।

पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी पर शाहनवाज हुसैन का बड़ा हमला

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता शाहनवाज हुसैन ने पंजाब कांग्रेस में चल रहे कथित अंदरूनी मतभेदों को लेकर कटाक्ष किया है। उन्होंने दावा किया कि पंजाब में पार्टी कई गुटों में बंट चुकी है और राज्य के नेता केंद्रीय नेतृत्व के फैसलों को चुनौती दे रहे हैं। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा, पंजाब में कांग्रेस कई गुटों में बंट गई है। वहां के नेता अब पार्टी इंचार्ज को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और भूपेश बघेल के खिलाफ भी बगावत हो गई है। पंजाब में कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व के फैसले को नहीं मानने का तय किया है। फैसले के खिलाफ भी बगावत हो रही है। शाहनवाज हुसैन ने कहा, ष्यह आपस में नहीं लड़ रहे हैं बल्कि केंद्रीय नेतृत्व को भी चुनौती दी जा रही है। इससे एक बात साफ हो गई है, जहां भी कांग्रेस है, वहां उसके नेता आपस में बंटे हुए हैं। राज्यों के अंदर बंट हुए नेताओं को ही कांग्रेसी कहा जाता है। उन्होंने कहा, ष्जब किसी भी दल में अंदरूनी मतभेद होता है तो लोग कहते हैं कि ये लोग कांग्रेस की तरह व्यवहार कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग टुकड़े–टुकड़े में बंटे होते हैं।ष इसी बीच, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की ओर से राज्य में सूखे की स्थिति का जायजा लेने के लिए केंद्र से एक टीम भेजने की मांग पर शाहनवाज हुसैन ने कहा, कर्नाटक सरकार लोगों की चिंताओं पर ध्यान नहीं दे रही है।

विद्या, कौशल और स्वास्थ्य से ही राष्ट्र का विकास- पीएम मोदी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बुधवार को सुभाषित शेयर किया। प्रधानमंत्री की ओर से सोशल मीडिया पर लिखा गया, विद्या से विवेक, कौशल से विकास और उत्तम स्वास्थ्य से हर संकल्प को सिद्धि मिलती है। आज हमारे युवा इन्हीं गुणों को आत्मसात कर देश की पहचान को और सशक्त बना रहे हैं। लाभानां श्रेय आरोग्यं सुखानां तुष्टिरुत्तमा। भी साझा किया है, जिसका हिंदी अर्थ है कि सभी श्रेष्ठ गुणों में कौशल सबसे उत्तम है, सभी धनों में विद्या सबसे बड़ी संपत्ति है, सभी लाभों में उत्तम स्वास्थ्य सबसे बड़ा लाभ है और सभी सुखों में संतोष सबसे श्रेष्ठ है। बीते दिन मंगलवार को सुभाषित शेयर करते हुए पीएम मोदी ने लिखा था, श्लोक का हिंदी अर्थ है कि जिस प्रकार सूर्य अपनी प्रकाश के बिना दृष्टिगोचर नहीं होता, उसी प्रकार प्रकाश की सूर्य के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता। इस प्रकार, सूर्य और प्रकाश का संपूर्ण अस्तित्व एवं शक्ति एक–दूसरे पर पूर्णतरू आश्रित हैं। प्रधानमंत्री की ओर से सोमवार को सोशल मीडिया पर सुभाषित शेयर करते हुए लिखा गया था, जब चौतरफा विकास के साथ हर देशवासी के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन सुनिश्चित होता है, तब राष्ट्र की प्रगति को भी नई गति मिलती है। इसी प्रेरक भावना के साथ हम भारत के सामर्थ्य को निरंतर मजबूती देने में जुटे हुए हैं। इस श्लोक का हिंदी अर्थ है कि कन्याओं के हितों की समुचित व्यवस्था करना, नई पीढ़ी के संरक्षण एवं विकास को सुनिश्चित करना तथा राष्ट्र की एकता, सुरक्षा, समृद्धि और सुव्यवस्थित संचालन के लिए निरंतर आवश्यक प्रबंधन करना, ये प्रत्येक जनप्रतिनिधि के नित्य कर्तव्य हैं।

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली

नई दिल्ली, (एजेंसी)। मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई। अब अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। श्रीकृष्ण जन्मभूमि से जुड़े मुख्य विवाद के साथ ही इस मामले में हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल तमाम याचिकाओं मे कौन सी याचिका रिप्रजेंटेटिव शूट बने, इस मुद्दे पर भी सुनवाई होनी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शूट नंबर 17 को रिप्रजेंटेटिव शूट माना था। हिन्दू पक्ष के दूसरे वादियों का कहना है कि उनके शूट अलग मुद्दे और दलीलों पर आधारित है, इसलिए केवल शूट संख्या 17 को रिप्रजेंटेटिव शूट नहीं माना जा सकता है। यह विवाद श्री कृष्ण जन्मभूमि और उसके निकट स्थित शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद उस स्थान पर बनी है जो भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है। हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण 17वीं सदी में औरंगजेब के शासनकाल में श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर बने प्राचीन केशवदेव मंदिर को तोड़कर किया गया था। उनका कहना है कि यह स्थल भगवान कृष्ण का जन्मस्थान है। दूसरी ओर, मुस्लिम पक्ष मस्जिद की ऐतिहासिक और कानूनी वैधता का दावा करता है। इस विवाद में मंदिर की जमीन पर स्वामित्व, पूजा का अधिकार और स्थल की पुरातात्विक जांच जैसे मुद्दे शामिल हैं। मस्जिद पक्ष का कहना है कि 1968 के समझौते के तहत यह विवाद पहले ही सुलझ चुका है। इसके पहले 5 जुलाई को शाही ईदगाह कमेटी के सेक्रेटरी और वकील तनवीर अहमद ने लोगों से अपील की थी।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 'सौश्रुतम् 2026' का उद्घाटन किया, आयुर्वेद में वैज्ञानिक शोध पर दिया जोर

नई दिल्ली, (एजेंसी)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने मंगलवार को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (।प्प्।), नई दिल्ली में 'सौश्रुतम् 2026' अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया। सुश्रुत जयंती के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने नए एमआरआई सेक्शन का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने आयुर्वेद जगत से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आचार्य सुश्रुत, जिन्हें शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है, ने सदियों पहले सर्जरी के क्षेत्र में क्रांतिकारी योगदान दिया था। उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी, मोतियाबिंद, ट्यूमर उपचार और ईएनटी सर्जरी सहित कई जटिल शल्य तकनीकों की शुरुआत की। राष्ट्रपति ने कहा कि आचार्य सुश्रुत द्वारा रचित 'सुश्रुत संहिता' ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को चिकित्सा विज्ञान की नई दिशा प्रदान की। उन्होंने कहा कि मानव कल्याण से जुड़ी हमारी पारंपरिक ज्ञान प्रणाली को समयानुकूल आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़कर समाज के हित में आगे बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद का समग्र जीवन दृष्टिकोण मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर है और इसे वर्तमान समय में भी प्रासंगिक एवं प्रभावी बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत सरकार आयुर्वेद और योग को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाने के साथ–साथ आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा की परंपरा को वैज्ञानिक मानकों पर प्रमाणित करने के प्रयास कर रही है।

उपराष्ट्रपति ने मंसूर अली खान और रजनीश अग्रवाल को दिलाई राज्यसभा की शपथ

नई दिल्ली, (एजेंसी)। संसद भवन में बुधवार को आयोजित एक समारोह में भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने दो नवनिर्वाचितध पुनर्निर्वाचित राज्यसभा सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसकी जानकारी उपराष्ट्रपति कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म श्एक्सश के जरिए दी। शपथ लेने वाले सदस्यों में कर्नाटक से कांग्रेस के सांसद मंसूर अली खान और मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रजनीश कुमार अग्रवाल शामिल हैं। मंसूर अली खान कर्नाटक से राज्यसभा सांसद हैं। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होने के साथ–साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) में केरल और लक्षद्वीप के सचिव की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। इसके अलावा, वह एक शिक्षाविद के रूप में भी अपनी पहचान रखते हैं। वहीं, रजनीश कुमार अग्रवाल मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने भाजपा संगठन में लंबे समय तक कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। वह भाजपा मध्य प्रदेश के प्रदेश सचिव रह चुके हैं। इससे पहले उन्होंने बूथ मैनेजमेंट प्रभारी, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता, भारतीय जनता युवा मोर्चा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, प्रदेश महासचिव, प्रदेश उपाध्यक्ष और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के प्रदेश सचिव जैसे अहम पदों पर भी कार्य किया है। इस अवसर पर मध्य प्रदेश भाजपा ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म श्एक्सश पर पोस्ट कर रजनीश कुमार अग्रवाल को बधाई दी। पार्टी ने लिखा कि मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश मंत्री रजनीश कुमार अग्रवाल ने आज संसद में मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। दोनों सांसदों के शपथ ग्रहण के साथ ही उन्होंने औपचारिक रूप से राज्यसभा में अपनी नई जिम्मेदारियों का निर्वहन शुरू कर दिया है। संसद के आगामी सत्रों में दोनों सदस्य अपने–अपने राज्यों और राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करते हुए सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे।

फडणवीस के घर आधी रात की सियासी मुलाकात

मुबई, (एजेंसी)। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने आधिकारिक आवास पर सत्तारूढ़ एनसीपी और विपक्षी एनसीपी (शरद पवार गुट) के नेताओं की देर रात मुलाकात की। इस मुलाकात ने राज्य में राजनीतिक समीकरण बदलने की अटकलों को हवा दे दी है। यह बैठक ऐसे समय हुई है जब कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने दावा किया है कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी एसपी और डीएमके से संपर्क साध रही है, ताकि संसद के मानसून सत्र में पेश किए जाने वाले 131वें संविधान संशोधन विधेयक के लिए उनका समर्थन हासिल किया जा सके। इसके साथ ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के दोनों गुटों के संभावित विलय को लेकर भी राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है। सूत्रों के मुताबिक, एनसीपी एसपी के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल ने मंगलवार देर रात मुंबई स्थित मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास श्वर्षाश में देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। दावा किया गया कि यह मुलाकात सांगली जिले की उनकी उरण–इस्लामपुर विधानसभा सीट से जुड़े एक मुद्दे को लेकर हुई थी। गौरतलब है कि मंगलवार को ही सत्तारूढ़ एनसीपी के नेताओं प्रफुल्ल पटेल तथा सुनील तटकरे ने भी मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की थी, लेकिन जयंत पाटिल और प्रफुल पटेल और सुनील तटकरे की मुलाकात एक साथ नहीं हुई। हालांकि, सूत्रों ने इस बारे में विस्तार से जानकारी देने से इनकार कर दिया। सरकार मानसून सत्र में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक पेश करने की तैयारी में है। इस विधेयक में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने और परिसीमन प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने वाला है।कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने मंगलवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में दावा किया, श्टीएमसी को तोड़ने के बाद बीजेपी कथित तौर पर एनसीपी एसपी और डीएमके को साधने की कोशिश कर रही है, ताकि विफल रहे विधेयक के नए स्वरूप के समर्थन के लिए जरूरी वोट जुटाए जा सकें। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री चिदंबरम ने दोनों क्षेत्रीय दलों से इस विधेयक का समर्थन नहीं करने की अपील की। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा फॉर्मूले के तहत होने वाला परिसीमन उन राज्यों के अधिकारों के साथ गंभीर अन्याय करेगा।

गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल को जन्मदिन पर मिली शुभकामनाओं की सौगात

नई दिल्ली, (एजेंसी)। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल को जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा," गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल को उनके जन्मदिन पर बहुत–बहुत शुभकामनाएं। वे गुजरात को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने और लोगों की उम्मीदों को पूरा करने में सबसे आगे हैं। मैं उनके दीर्घायु, स्वस्थ एवं सुखमय जीवन की कामना करता हूं।'' लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने एक्स पर पोस्ट किया, "गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को जन्मदिन पर हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य, प्रसन्न एवं मंगलमय जीवन की कामना करता हूं।" सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक्स पर लिखा, "गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और मंगलमय जीवन की प्रार्थना करता हूं।" केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक्स पर लिखा," गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल को उनके जन्मदिवस की हार्दिक शुभेच्छा। प्रदेश में हो रहे निरंतर विकास तथा जनता के कल्याण के प्रति आपकी कटिबद्धता सराहनीय है, आशा है कि प्रभु श्री राम की कृपादृष्टि आप पर सदैव बनी रहें।" केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने एक्स पर पोस्ट किया, "गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भगवान सोमनाथ महादेव से आपके उत्तम स्वास्थ्य, सुदीर्घ और यशस्वी जीवन की कामना करता हूं।

देश आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है – जयराम रमेश

नई दिल्ली, (एजेंसी)। थोक महंगाई (डब्ल्यूपीआई) जून में बढ़कर 9.87 फीसदी पहुंचने के बाद कांग्रेस ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण देश धीरे–धीरे आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है। कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब भी मांगा और कहा कि 12 साल तक सरकार चलाने के बाद इस आर्थिक स्थिति की जिम्मेदारी उन्हें ही लेनी चाहिए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर हिंदी में पोस्ट करते हुए कहा कि कांग्रेस पिछले कई महीनों से सरकार को आर्थिक हालात को लेकर लगातार आगाह करती रही है, लेकिन सरकार ने समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि जून में थोक महंगाई 44 महीनों के सबसे ऊंचे स्तर 9.87 फीसदी पर पहुंच गई है। वहीं, ईंधन और बिजली की कीमतों में 27.4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही कृषि बुवाई तीन साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। उनका कहना है कि महंगाई और बेरोजगारी की मार से आम लोग परेशान हैं, जबकि किसान सरकार की नीतियों और प्रतिकूल मौसम की दोहरी मार झेल रहे हैं। जयराम रमेश ने कहा कि बढ़ती महंगाई से उद्योगों की लागत भी लगातार बढ़ रही है। उनका आरोप है कि जब अर्थव्यवस्था के लगभग सभी प्रमुख संकेतक चिंता बढ़ा रहे हैं, तब सरकार हालात संभालने के बजाय लोगों का ध्यान भटकाने में लगी हुई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार महंगाई पर नियंत्रण करने के बजाय वास्तविक आंकड़ों को छिपाने की कोशिश कर रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जून में थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित महंगाई बढ़कर 9.87 फीसदी हो गई, जो मई में 9.68 फीसदी थी। यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से खाद्य और गैर–खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तेजी के कारण हुई। नए आंकड़े 2022–23 को आधार वर्ष मानकर जारी किए गए हैं। जून में खाद्य महंगाई बढ़कर 5.49 फीसदी हो गई, जो मई में 3.60 फीसदी थी। एल नीनो के असर से कम बारिश होने के कारण खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तेजी दर्ज की गई।

डीएमआरसी की हाईस्पीड रेल परियोजना अधूरी, डीपीआर से पहले नए अध्ययन जरूरी – सीएम सतीशन

नई दिल्ली, (एजेंसी)। मेट्रो मैन ई. श्रीधरन के मार्गदर्शन में दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) द्वारा तैयार किए गए प्रस्तावित हाई–स्पीड रेल कॉरिडोर को रद्द नहीं किया गया है लेकिन केरल सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि परियोजना तभी आगे बढ़ेगी जब महत्वपूर्ण तकनीकी और आर्थिक अध्ययन पूरे हो जाएंगे। बुधवार को कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने ये बात कही। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन कहा कि सरकार द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति ने डीएमआरसी की रिपोर्ट की जांच की और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं। समिति ने पाया कि यद्यपि डीएमआरसी की रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करती है, इसे एक व्यापक परियोजना रिपोर्ट नहीं माना जा सकता। प्रस्ताव में अनिवार्य पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) शामिल नहीं है और न ही इसमें कॉरिडोर के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण की सीमा निर्दिष्ट की गई है। सीएम सतीशन ने कहा कि सरकार पहले परियोजना की वित्तीय और परिचालन व्यवहार्यता का विस्तृत अध्ययन करेगी, जिसमें माल ढुलाई और रसद आवागमन की संभावना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि केवल यात्री राजस्व से परियोजना को आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाना पर्याप्त नहीं होगा, इसलिए राजस्व के अतिरिक्त स्रोत आवश्यक हैं। इन प्रारंभिक अध्ययनों के पूरा होने के बाद ही सरकार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करेगी, जो कार्यान्वयन संबंधी अंतिम निर्णय का आधार बनेगी। मुख्यमंत्री सतीशन ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार इतनी बड़ी परियोजना को शुरू करने से पहले सतर्क और पारदर्शी दृष्टिकोण अपनाएगी। उन्होंने कहा, श्हम पिछली वामपंथी सरकार की बहुचर्चित के–रेल परियोजना में हुई गलतियों को दोहराना नहीं चाहते, जिसे अंततः रद्द करना पड़ा। सरकार आगे की राह तय करने से पहले पूरी तरह विचार करेगी। इस बीच, मंत्रिमंडल ने सभी विभागों में परियोजना निगरानी को मजबूत करने का भी निर्णय लिया।

संपादकीय

मंदिर में चोरी और नेहरू जी

राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला अब केंद्र और उत्तरप्रदेश की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल बनता जा रहा है। विपक्ष तो इस मुद्दे पर लगातार सवाल उठा ही रहा है, अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी इस मामले पर अपनी चिंता सार्वजनिक तौर पर व्यक्त की है। संघ की वार्षिक श्अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठकश हाल ही में कर्नाटक के बेलगावी में खत्म हुई। बैठक में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे की गिनती में हुई गड़बड़ी की घटना पर दुख जताया गया। उत्तरप्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस मामले में एक एसआईटी गठित कर जांच शुरु की है, जिस पर संघ ने भरोसा जताया कि एसआईटी और पुलिस की कार्रवाई किसी ठोस नतीजे तक पहुंचेगी। संघ ने कहा कि श्तीर्थ क्षेत्र न्यासश पक्का करे कि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो जिससे राम मंदिर के प्रति सभी राम भक्तों की श्रद्धा और गहरी आस्था को ठेस पहुंचे।श वैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने भी स्पष्ट किया है कि इस मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ बेहद सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।लेकिन बड़ा सवाल तो यही बना हुआ है कि जिस न्यास का गठन भाजपा सरकार की देखरेख और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जानकारी में हुआ, वहां करोड़ों की चोरी करने की किसी की भी हिम्मत कैसे हुई। दो ही स्थितियों में ऐसा मुमकिन है, या तो प्रधानमंत्री ने राम मंदिर का राजनैतिक उपयोग करने के बाद वहां के संचालन पर ध्यान नहीं दिया या फिर उन्हें सब कुछ पता होते हुए भी उन्होंने इस तरफ अनदेखी की। सच्चाई क्या है यह तो खुद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बताएंगे।लेकिन कम से कम इन पंक्तियों के लिखे जाने तक इस पूरे प्रकरण पर नरेन्द्र मोदी ने कुछ नहीं कहा है। राम मंदिर के लिए आडवानी द्वारा निकाली गई रथयात्रा से लेकर बाबरी मस्जिद तोड़कर उसी जगह पर मंदिर के लिए भूमिपूजन करने, फिर मंदिर का उद्घाटन, प्राण प्रतिष्ठा करने तक नरेन्द्र मोदी का चेहरा ही आगे रहा। रथयात्रा में उन्होंने संघ और भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते समन्वयक के तौर पर काम किया था, लेकिन जब उस बीज की फसल लहलहाई तो सबसे ज्यादा लाभ नरेन्द्र मोदी के खाते में ही आया। हर चुनाव में उन्होंने यह दावा किया कि जहां वादा किया था, वहीं मंदिर बनवाया। तो अब हिंदुओं की आस्था पर इतनी बड़ी चोट की गई है, तो क्या नरेन्द्र मोदी को दर्द नहीं हो रहा है, यह सवाल तो उठेगा ही। जब संघ के लोग अफसोस जाहिर कर सकते हैं, जब नरेन्द्र मोदी के पूर्व प्रधान सचिव और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी रहे नृपेंद्र मिश्रा इस सार्वजनिक चोरी पर दुख जता चुके हैं, तो नरेन्द्र मोदी को बोलने से कौन रोक रहा है।ध्यान रहे कि 2024 में प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि श्राम राष्ट्र हैं और देव देश हैं।श हालांकि यह विचार संविधान की धर्मनिरपेक्ष भावना के खिलाफ था, फिर भी अगर मोदी को अपने कहे पर यकीन था तो अब अपने राष्ट्र और देश पर चोरों की कुदृष्टि देखकर भी वे शांत कैसे हैं। नरेन्द्र मोदी के समर्थकों ने हाल ही में उनकी सत्ता के 12 साल पूरे होने पर इस बात की खुशी मनाई कि मोदी ने प.नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया।

नेपाल का दूसरा जेन-जी संकट

असद मिर्जा शाह की सरकार को यह समझने की जरूरत है कि जेन–जी की मूल मांग कभी भी सिर्फ सिंहदरबार में चेहरे बदलने की नहीं थीकृ यह ऐसी संस्थाओं की मांग थी जो नागरिकों, विशेष रूप से सबसे गरीबों के साथ, उचित प्रक्रिया के तहत व्यवहार करें। इस कसौटी पर खरा न उतरना नेपाल की अब तक की सबसे युवा सरकार को इस बात का एक उदाहरण बना सकता है। एक सरकार गिराने के दस महीने बाद, नेपाल की जेन–जी अब उसी सरकार के सामने खड़ी है जिसे उसने खुद बनाया। एक क्रूर बेदखली अभियान, एक चालक की आत्मदाह घटना और असहमति पर बढ़ती कार्रवाई यह परख रही है कि क्या बालेन शाह की श्नई राजनीतिश पुरानी राजनीति से अलग है।नेपाल एक असहज पुनरावृत्ति देख रहा है। के.पी. शर्मा ओली को सत्ता से हटाने वाले युवा विद्रोह के एक साल से भी कम समय बाद, वही पीढ़ी फिर से सड़कों पर है कृ इस बार उसी नेता के खिलाफ जिसे उसने सत्ता में बिठाने में मदद की थी। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह, वह रैपर–इंजीनियर–से–मेयर बने नेता जो मार्च 2026 में जेन–शी के गुस्से की लहर पर सवार होकर भारी जीत हासिल की, अब अपने कार्यकाल के पहले बड़े जन–विद्रोह का सामना कर रहे हैं। इस बार वजह भ्रष्टाचार या सोशल मीडिया प्रतिबंध नहीं, बल्कि बुलडोजर हैं।अप्रैल के अंत से, काठमांडू घाटी में बागमती और अन्य नदी किनारों पर बसी झुग्गी–झोपड़ी और अनियोजित बस्तियों के खिलाफ सरकार के बेदखली अभियान ने 2,600 से अधिक परिवारोंकृ लगभग 15,000 लोगोंकृ के घर ध्वस्त कर दिए हैं। इसे अतिक्रमित सार्वजनिक भूमि वापस लेने की मुहिम के रूप में पेश किया गया था, और शुरुआत में इसे व्यापक समर्थन भी मिला थारू यहां तक कि आरएसपी के चुनावी घोषणापत्र में भी उपग्रह मानचित्रण और बायोमेट्रिक सत्यापन के जरिए श्वास्तविकश भूमिहीन परिवारों को अवसरवादी अतिक्रमणकारियों से अलग करने का वैज्ञानिक तरीका अपनाने का वादा किया गया था।जिस बात ने आक्रोश पैदा किया है, वह नदी किनारों को साफ करने का सिद्धांत नहीं, बल्कि उसका क्रम हैकृ पहले बेदखली, फिर पुनर्वास, अगर हुआ तो। लगभग 325 परिवारों को अस्थायी होल्डिंग सेंटरों में स्थानांतरित किया गया, जिनमें से कई बाद में बाढ़ की चपेट में आ गए, सबसे स्पष्ट रूप से कीर्तिपुर में। इस महीने की शुरुआत में सरकार ने निवासियों को इन आश्रयों को भी खाली करने का आदेश दिया, हालांकि कई ने कहा कि उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। गुस्सा तब चरम पर पहुंच गया जब एक चालक, गणेश नेपाली ने नगर पुलिस के साथ विवाद के बाद खुद को आग लगा लीकृ यह घटना अब प्रदर्शनकारियों के लिए गरीबों के प्रति राज्य की उदासीनता का प्रतीक बन गई है।संयुक्त राष्ट्रीय स्क्वाटर मोर्चा ने तब से श्गरीबों पर अत्याचार बंद करोश जैसे नारों वाले बैनरों के तहत मार्च आयोजित किए हैं, जबकि वे युवा कार्यकर्ता जिन्होंने कभी शाह के उभार की सराहना की थी, अब उनके प्रशासन पर भूमिहीनों को एक संवैधानिक दायित्व के बजाय एक असुविधा मानने का आरोप लगा रहे हैंकृ उनके अनुसार, यह सितंबर 2025 में जेन–जी द्वारा लड़ी गई जवाबदेही और समावेशन की भावना के साथ विश्वासघात है। सरकार की प्रतिक्रिया बालेन शाह के प्रशासन ने इन बेदखलियों को काफी हद तक लंबे समय से लंबित भूमि प्रबंधन के रूप में उचित ठहराया है, और यह दावा किया है कि वास्तविक भूमिहीन परिवारों और मुनाफे के लिए सार्वजनिक या निजी भूमि पर कब्जा करने वाले अतिक्रमणकारियों के बीच अंतर बनाए रखा जा रहा है। लेकिन इसके बाद के घटनाक्रम को संभालने के तरीके ने नीति से भी अधिक आलोचना खींची है। पुलिस ने कई जेन–जी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया हैकृ जिनमें माजिद अंसारी, सरिस्मा थापा और नेल्सन घतानी शामिल हैंकृ जब वे बाढ़ के बाद हालात दर्ज करने के लिए कीर्तिपुर होल्डिंग सेंटर पहुंचे थे।नेपाल पुलिस के प्रवक्ता अबी नारायण काफले का कहना है कि कार्रवाई केवल उन्हीं के खिलाफ की जाती है जो श्पुलिस के काम में बाधा डालते हैं, अशांति भड़काते हैं या सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालते हैं,श और वैध विरोध का सम्मान किया जाता है। अधिकार समूह इसे अलग तरह से देखते हैंरू महिला मानवाधिकार रक्षक राष्ट्रीय गठबंधन ने जिसे वह श्अमानवीय व्यवहारश और श्गैरकानूनी हिरासतश कहता है।

प्रधानमंत्री मोदी को मिले पुरस्कारों पर गार्जियन की हताशा

योगेंद्र

दा गार्जियन अखबार ने मोदी और भारत की छवि धूमिल करने के लिए एक अंग्रेजी मे एक लेख लिखा। जिसका सारांश यह है कि कोई झूठे भी पुरस्कार देने के लिए बुलाए तो प्रधानमंत्री मोदी दौड़े दौड़े चले जाते हैं। मतलब यह अखबार कहना चाह रहा कि मोदी पुरस्कार के भूखे हैं, साथ ही यह भी जताने की कोशिश कर रहा है, जिन देशों ने मोदी को उनकी विदेश यात्रा के दौरान पुरस्कार दिए, उनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी को इन देशों ने फिजूल में पुरस्कार दिए हैं। गार्जियन ने यह लेख लिख कर मोदी सहित भारत का तो अपमान किया ही है, साथ मोदी को पुरस्कार देने वाले उन देशों के नागरिकों, पुरस्कारों और उन देशों के राष्ट्रप्रमुखों का भी अपमान किया है। इस लेख की भड़ास के बावजूद पीएम मोदी को पुरस्कारों का सिलसिला थम नहीं रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान 'बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया' मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। यह सम्मान पीएम मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने प्रदान किया। वर्ष 2016 से अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एशिया, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के देशों से ऐसे 34 सम्मान मिल चुके हैं। यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री को मिले सम्मानों में सबसे अधिक हैं। इनमें से कुछ सम्मान सदियों पुराने हैं, जबकि कुछ सम्मान संबंधित देशों की सम्मान प्रणाली में हाल ही में शामिल किए गए हैं। गार्जियन का यह लेख में भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने का कुत्सित प्रयास है। विश्व का बड़ा और प्रभावशाली शायद ही कोई देश बचा होगा जिसके प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने मोदी और भारत की तारीफ नहीं की होगी। दरअसल यह तारीफ पाश्चात्य मीडिया पचा नहीं पा रहा है, पचा इसलिए भी नहीं पा रहा है कि भारत न सिर्फ घरेलू स्तर पर बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी तरक्की के झंडे गाढ़ रहा है। चंद्रयान और मंगलयान मिशन की कामयाबी इसके बड़े उदाहरण हैं। जो विकसित देश भी हासिल नहीं कर सके। यह अखबार यह भी भूल गया कि जब कोरोना काल में पूरी दुनियां में हाहाकार मचा हुआ था, तब भारत ने ही कोरोना वैक्सीन दर्जनों देशों को निशुल्क भेज कर करोड़ों लोगों की जाने बचाने का काम किया था। क्या ऐसे परोपकारी कार्यों के लिए उन्हें विदेशी पुरस्कार नहीं दिया जा सकता। गार्जियन ने इसका जिक्र कभी नही किया कि विश्व को मोदी नेतृत्व में भारत ने क्याकृक्या दिया है। भारत की यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस जैसी सस्ती और सुलभ डिजिटल पेमेंट प्रणाली नेपाल, भूटान, सिंगापुर, यूएई और मॉरीशस ने अपना लिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत की प्राचीन धरोहर योग को मोदी सरकार के प्रयासों से वैश्विक मान्यता मिलीघ्संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर वर्ष 21 जून को श्अंतरराष्ट्रीय योग दिवसश के रूप में मनाया जाता है। मोदी सरकार के प्रयासों से ही अफ्रीकी संघ को जी–20 का स्थायी सदस्य बनाया गया। भारत ने प्राकृतिक आपदा के दौरान विश्व के देशों के साथ कंधे से कंधा मिला कर खड़ा रहा है। तुर्किये और सीरिया में आए भूकंप के दौरानश्मिशन सागरश्औरश्ऑपरेशन दोस्तश्के जरिए विश्व स्तर पर मानवीय सहायता पहुंचाई गई। वेनेजुएला में विनाशकारी भूकंप के बाद ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत बचाव दल और पोर्टेबल अस्पताल भेजे गए। म्यांमार में ऑपरेशन ब्रह्मा (2025) और ऑपरेशन सहायता (2008) के तहत भूकंप व चक्रवात के दौरान भारी राहत सामग्री व चिकित्सा सुविधाएँ दी गईं। श्रीलंका में सुनामी (2004) में ऑपरेशन रेनबो और चक्रवात (2025) में ऑपरेशन सागर बंधु के माध्यम से सहायता प्रदान की गई। भारतीय नौसेना ने हालिया समुद्री सुरक्षा अभियानों (मुख्य रूप से अरब सागर और अदन की खाड़ी) में 520 से अधिक लोगों की

जान बचाई है और ईरान, लाइबेरिया, माल्टा, और सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडाइन्स जैसे विभिन्न देशों के झंडे वाले जहाजों को समुद्री लुटेरों से सुरक्षित मुक्त कराया है। इन अभियानों की सबसे बड़ी खासियत यह रही है कि नौसेना ने बिना किसी राष्ट्रीय भेदभाव के, पाकिस्तानी और ईरानी नागरिकों सहित कई देशों के नाविकों को भी बचाया है। गार्जियन खासकर विदेशी मीडिया को कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन पर भारी परेशानी है। भारत में उन्हें यह उल्लंघन नजर आता है। अंग्रेजों ने भारत पर 200 साल राज किया। अंग्रेज शासकों ने इस अवधि में भारतीयों पर अत्याचारों के सारे रिकार्ड तोड़ दिए। अंग्रेज व्यापारी बन कर आए और तानाशाह बन बैठे, खूब लूट खसौट की और भारत से सारा मालमत्ता समेट कर चंपत हो गए। आज भी कोहिनूर का हीरा इन्हीं अंग्रेजों के पास है, जो यह बताता है कि किस तरह इन्होंने भारत में लूटपाट मचाई थी। ऐसे मानवाधिकारों के उल्लंघन गार्जियन जैसे अखबारों को दिखाई नहीं देते। मानवाधिकारों के इन विदेशी पैरोकारों को जलियांवाला बाग दिखाई नहीं देता, जहां निहत्थे प्रदर्शकारियों को चारों तरफ से घेर कर एक अंग्रेज अधिकारी डायर ने गोलियों से भून डाला था। गार्जियन को यह कभी दिखाई नहीं दिया कि किस तरह केंद्र सरकार ने मुसलमानों की भलाई का एक ऐतिहासिक काम किया, जिसे करने से पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री डरते रहे। देश की करोड़ों मुस्लिम महिलाओं को तलाक के बाद मिलने वाला कानून हक दिलवाया है। जिन्हें पहले पति तीन बार तलाक तलाक बोल कर धक्के खाने के लिए छोड़ दिया जाता था।कांग्रेस ने मुसलमानों के वोट के डर से सुप्रीम कोर्ट के शाह बानों के फैसले को ही पलट दिया था, जिसमें कोर्ट ने गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था, इसके खिलाफ तत्कालीन कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कानून बना दिया था। विदेशी अखबारों को तकलीफ हो रही है कि मोदी राज में कैसे मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, जब भारत ने ऐसे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया तब खीझ उतारने के लिए कह दिया कि मोदी पुरस्कार के लिए दौड़े चले आते हैं। जिला स्तर, वार्ड स्तर, राज्यस्तर या राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी और निजी क्षेत्र में पुरस्कार के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, इन्हें पाने के लिए लोग अपनी पूरी उम्र खपा देते हैं। उसमें भी जबरदस्त प्रतिस्पर्धा होती है, तब कहीं जाकर किसी एक का चयन किया जाता है।

ऐसे में देशों द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिये जाने वाले पुरस्कार का मापदंड कितने कठोर होगा, इसकी कल्पना ही की जा सकती है। इन पुरस्कारों में पुरस्कार देने वाली सरकार के साथ उन देशों के करोड़ों लोगों की भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। चलो मान भी लिया जाए कि किसी एक देश ने भारत से कुछ फायदा लेने के लिए कोई पुरस्कार दे दिया होगा, पर मोदी को तो दर्जनों देशों के सर्वोच्च पुरस्कार मिले हैं।

विदेश से लौटते ही मोदी का एक्शन, 2 दिन बाद बीजेपी में होने वाला है

अभिनय

इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी चीज की हो रही है तो वो है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के दफ्तर में हुए बड़े प्रशासनिक बदलाव की। पहले निजी सचिव अमर सिंह को हटाया गया। फिर आयुष शरण और शैलेश कुमार सिंह को भी उनके पदों से मुक्त कर दिया गया। ऐसे में सवाल यही है कि ऐसा क्या हुआ कि इतने बड़े स्तर पर एक साथ कार्रवाई करनी पड़ी। सरकार की तरफ से अभी तक इन अधिकारियों को हटाने की कोई आधिकारिक वजह नहीं बताई गई है। आदेश जारी हुए, अधिकारी हटाए गए लेकिन कारण सार्वजनिक नहीं किया गया। यही बात इस पूरे घटनाक्रम को सामान्य ट्रांसफर से अलग बनाती है। राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में मंत्रालयों और मंत्रियों के दफ्तर की कार्यप्रणाली की गहन समीक्षा कर रही है। जिन अधिकारियों के कामकाज को लेकर सवाल है, या जिनकी कार्यशैली सरकार की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर रही है उन पर एक्शन हो सकता है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि तो नहीं है। लेकिन लगातार हो रहे बदलावों ने इन अटकलों को जरूर हवा दे दिया है। चर्चा ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से लौटने के बाद सरकार कुछ और बड़े प्रशासनिक और राजनीतिक फैसले ले सकती है। विस्पर्स इन द कॉरिडोर वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार भूपेंद्र यादव को पता ही नहीं था कि उनके स्टॉफ को हटाया जा रहा है। उन्हें तब पता चला जब सचिवालय में चिट्ठी टाइप होने चली गई। अगर विस्पर्स इन द कॉरिडोर की खबर सच है तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक मामला है कि मंत्री ऑफिस में भी नहीं बताया गया। शैलेंद्र यादव को लेकर इंडियन एक्सप्रेस ने दावा किया है कि वो बहुत पुराने वक्त से भूपेंद्र यादव के साथ थे। आरएसएस के जमाने से वो जुड़े थे। एक महीना राजनीति में बहुत लंबा वक्त होता है। भूपेंद्र यादव लुटियंस दिल्ली के जिस बंगले में रहते हैं वो बंगला नंबर 9 है। इस बंगले में आज से करीब एक महीने पहले की बात है तृणमूल कांग्रेस के सारे बागी सांसद इसी बंगले में बैठे थे। उस वक्त ये चर्चा चल रही थी कि 20 की संख्या कैसे पूरी होगी। लेकिन उस बंगले से आई तस्वीर में कहीं भी भूपेंद्र यादव नजर नहीं आ रहे थे। कहा ये भी गया कि भूपेंद्र यादव लाइमलाइट में नहीं आना चाहते थे और इसलिए उन्होंने सांसदों की तस्वीरें खिंचवाई और बीजेपी का आंकड़ा 300 के पार कर दिया। एक व्यक्ति जो बीजेपी को बंगाल जिताकर आया हो। जो टीएमसी को तोड़ रहा हो। उसके सारे के सारे स्टॉफ को पीएमओ के आदेश पर हटा दिया गया। दावे के अनुसार भूपेंद्र यादव को बाद में दी जा रही है। भूपेंद्र यादव एक पॉवरफुल मंत्री हैं और बीजेपी के नंबर 2 के नेता के बहुत करीबी माने जाते हैं। संगठन के अंदर बहुत अच्छी पकड़ है। राजनीतिक हलकों में दबी जुबान से ये भी कहा जा रहा है कि भूपेंद्र यादव का इस्तीफा भी हो सकता है। पीएम मोदी 12 जुलाई को अपने विदेश दौरे से लौट रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी ने साफ कहा कि हम एक गोल रखते हैं और उसके पूरा होते ही दूसरा बड़ा गोल रखते हैं। पीएम मोदी एक टारगेट ओरिएंटेड लीडर हैं। वो टारगेट सेट करते हैं और उस टारगेट पर फिट नहीं बैठने पर श्पूरे घर को बदल डालोश वाली नीति अपनाते हैं। 12 जुलाई को एक बैठक होने वाली है। उसके बाद बड़े बड़े फैसले हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से तो ये भी दावा किया जा रहा है कि राजनाथ सिंह को आगामी राष्ट्रपति के कार्यकाल समाप्त होने के बाद ये जिम्मेदारी दी जा सकती हैं। वहीं नितिन गडकरी के गवर्नर बनाए जाने की भी चर्चा है। इसके अलावा भी कैबिनेट में बड़े बदलाव हो सकते हैं। कैबिनेट में बदलाव तो एक हफ्ते पहले ही हो जाना था। लेकिन एनडीए की सहयोगी दलों को भी मंत्रिमंडल में जगह दिया जाना है और उसके लिए नेगोसिएशन का दौर चल रहा था। कौन सा विभाग किसके पास जाए इसको लेकर ये उस वक्त छोड़ा लंबा खिंच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते सप्ताह पचपदरा में देश की सबसे आधुनिक और पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी का उद्घाटन किया। इस प्लांट का उद्घाटन पहले ही करना था। लेकिन जब प्रधानमंत्री का कार्यक्रम बना तो वहां मालूम चला कि आग लग गई। सूत्रों के हवाले से बताया जाता है कि उस वक्त दो प्रशासनिक अधिकारियों के हटाए जाने को कहा गया था। लेकिन उस वक्त भी राजनस्थान की राजनीति को दिल्ली से चलाने वाले एक बड़े नेता ने मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन इसके बाद पेड़ लगाने का कार्यक्रम रखा गया। सूत्रों के अनुसार पीएमओ की तरफ से कहा गया था कि वहां पर दो पेड़ की बातचीत चल रही थी और उस पेड़ में पीपल नहीं लगना था तो जो पेड़ लगाना था वो खेजड़ी का लगाना था। लेकिन हुआ इसका उल्टा। पौधारोपण के बाद प्रधानमंत्री के आधिकारिक एक्स हैंडल से तस्वीरें साझा करते हुए लिखा गया कि पर्यावरण संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है और उन्हें पचपदरा में श्खेजड़ीश का पौधा लगाने का सौभाग्य मिला है। इस पोस्ट के सामने आते ही आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को टैग करते हुए एक्स पर एक पोस्ट लिखी। बेनीवाल ने तंज कसते हुए सवाल किया मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आज आप राजस्थान के पचपदरा आए, वृक्षारोपण भी किया, क्या आपकी सरकार ने खेजड़ी की नई किस्म का आविष्कार किया है या फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी ने पीपल को खेजड़ी बताकर आपसे पौधारोपण करवा दिया ? हनुमान बेनीवाल की ओर से सोशल मीडिया पर यह दावा किए जाने के बाद कि लगाया गया पौधा खेजड़ी नहीं बल्कि पीपल का है, इंटरनेट पर यह मुद्दा तेजी से वायरल हो गया। इसके कुछ समय बाद ही प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल से उस संबंधित पोस्ट और तस्वीरों को हटा दिया गया। फिर यह पूछा गया कि जब खेजरी तय हुआ तो किसने बदला? कहा जाता है न कि जब वक्त उल्टा चलता है तो यही हो जाता है कि फिर एक के बाद एक गलतियां जो है वो सामने आने लगती है। प्लांट के अंदर पिछली बार भी बवाल मचा था। आग लगने की वजह से तो यही पूछा गया कि भाई फिर अब यह किसकी जिम्मेदारी है? फिर पेड़ वाला विवाद तो राजस्थान में भी कुछ बदलाव अगर देखने को मिल जाएं तो आश्चर्य नहीं होगा।

विपक्ष को तोड़ने की भाजपा की राष्ट्रीय राजनीतिक रणनीति घृणित

डॉ. ज्ञान

राजनीति समाचार पत्र राज्यसभा में भाजपा की अपनी संख्या 114 है, जो भाजपा के टिकट पर दोबारा चुने जाने वाले पूर्व टीएमसी सांसदों के आने के बाद 117 हो जाएगी। हालांकि, इससे राज्यसभा में भाजपा की संख्या पार्टी के इतिहास में सबसे ज्यादा हो जाएगी, फिर भी यह बहुमत के आंकड़े से छह कम होगी, जिसकी उसे सख्त

जरूरत है। भारत की संसद–राज्यसभा और लोकसभा दोनों– में अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सत्ताधारी भाजपा ने विपक्षी राजनीतिक दलों को तोड़ने की राष्ट्रीय राजनीतिक रणनीति अपनाई है। 9 जुलाई 2026 को यह रणनीति बेशर्मी की हद तक पहुंच गई, जिससे लोकतंत्र और निष्पक्ष, नैतिक राजनीति को पसंद करने वालों में गहरी नाराजगी पैदा हुई है। पार्टी ने राज्यसभा के लिए तीन टीएमसी नेताओं को दोबारा नामांकित किया है, जिन्होंने 8 से 11 जून के बीच सदन से इस्तीफा दे दिया था।ये पूर्व टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर रे, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबारिक हैं। भाजपा ने पिछले महीने ही उनसे राज्यसभा से इस्तीफा दिलवाया था, क्योंकि वह सदन में टीएमसी को तोड़ नहीं पा रही थी। राज्यसभा में टीएमसी के 13 सांसद थे, और किसी अन्य पार्टी (जैसे भाजपा) में विलय या अलग समूह बनाने के लिए 9 सांसदों की जरूरत थी। बिना सीट गंवाए कानूनी रूप से अलग होने के लिए, पार्टी के चुने हुए विधायकोंध्सांसदों में से दो–तिहाई का किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी में विलय करने या नई राजनीतिक इकाई बनाने पर सहमत होना जरूरी है।जब भाजपा ऐसा कानूनी रूप से नहीं कर पाई, तो उसने उन सांसदों से सदस्यता से इस्तीफा दिलवा दिया, जिससे राज्यसभा में सीटें खाली हो गईं। इसके बाद, खाली सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव की जरूरत पड़ी और चुनाव की तारीख 24 जुलाई घोषित की गई। फिर भाजपा ने उन्हीं तीन सांसदों को पार्टी का टिकट दिया, जब वे 9 जुलाई को औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा ने अभी मई में ही पश्चिम बंगाल का चुनाव जीता है और विधानसभा में उसके पास 208 सीटें हैं। इसलिए, भाजपा तीनों सांसदों को फिर से राज्यसभा भेजने की स्थिति में है, लेकिन अब भाजपा सांसद के तौर पर।हालांकि, लोकसभा में भाजपा 28 में से 20 टीएमसी लोकसभा सांसदों को एक अलग इकाई बनाने के लिए मनाने में सफल रही। इस तरह लोकसभा में टीएमसी टूट गई, और अलग हुए समूह का विलय एनसीपीआई में हो गया, जो पूर्वोत्तर की एक कम जानी–मानी पार्टी है, हालांकि मूल रूप से पश्चिम बंगाल में रजिस्टर्ड है। ध्यान देने वाली बात है कि एनसीपीआई, भाजपा का समर्थन करती है और एनडीए का हिस्सा है। लोकसभा स्पीकर ने अभी तक इस विलय को मंजूरी नहीं दी है, और टीएमसी इसका विरोध करते हुए मांग कर रही है कि बागी सांसदों को अयोग्य घोषित किया जाए।वहीं कोलकाता में, टीएमसी के 80 में से 60 से ज्यादा विधायकों ने रितब्रत बनर्जी के नेतृत्व में एक अलग गुट बना लिया है, जिन्हें विधानसभा स्पीकर ने विपक्ष का नेता माना है। स्पीकर के फैसले के आधार पर, इस अलग हुए गुट ने दावा किया है कि वे ही श्असली टीएमसीश हैं और उन्होंने मान्यता के लिए भारत के चुनाव आयोग में आवेदन भी किया है। ममता बनर्जी को भाजपा की इस साज़िश का मु+काबला करना होगा, ताकि पार्टी की संस्थापक होने के नाते वह पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न अपने पास बनाए रख सकें। फिर भी, महाराष्ट्र का अनुभव बताता है कि न तो शरद पवार अपनी पार्टी एनसीपी का नाम और चुनाव चिह्न बचा पाए और न ही उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी शिवसेना का नाम और चुनाव चिह्न। यह सब भाजपा की उस पेंचीदा राजनीति की वजह से हुआ, जिस पर विपक्षी राजनीतिक दलों को तोड़ने और विपक्षी सरकारों को गिराने की रणनीति अपनाने का आरोप लगता रहा है। 2026 की शुरुआत में ही, भाजपा ने आप के 7 राज्यसभा सांसदों से अलग गुट बनवा कर उन्हें भाजपा में शामिल कर लिया था। पार्टी के अहम पदों से हटाए जाने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) के सात राज्यसभा सांसदों ने औपचारिक रूप से भाजपा का दामन थाम लिया। इन सांसदों में राघव चड्ढा, संदीप पाठक, डॉ. अशोक कुमार मित्तल, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, विक्रमजीत सिंह साहनी और राजिंदर गुप्ता शामिल हैं। इस बदलाव से उच्च सदन में आप की संख्या 10 से घटकर सि+र्फ तीन रह गई, जबकि भाजपा की संख्या बढ़कर 113 हो गई।फिलहाल, राज्यसभा में भाजपा की अपनी संख्या 114 है, जो भाजपा के टिकट पर दोबारा चुने जाने वाले पूर्व टीएमसी सांसदों के आने के बाद 117 हो जाएगी। हालांकि, इससे राज्यसभा में भाजपा की संख्या पार्टी के इतिहास में सबसे ज्यादा हो जाएगी, फिर भी यह बहुमत के आंकड़े से छह कम होगी, जिसकी उसे सख्त □रूरत है। राज्यसभा में बहुमत का आंकड़ा 123 है। फिर भी, तीन निर्दलीय सदस्य पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, और सात मनोनीत सदस्य भी हैं। कुल मिलाकर, उनकी संख्या 127 हो जाएगी, जो साधारण बहुमत से चार ज्यादा है। एनडीए में भाजपा के सहयोगियों के पास 26 और सांसद हैं, और इसलिए, राज्यसभा में एनडीए की कुल सीटें 153 होंगी। यह संख्या सदन में किसी भी संवैधानिक संशोधन को पास करने के लिए जरूरी दो–तिहाई बहुमत (164 सीटें) से 11 कम हैकृजिसे भाजपा नेतृत्व हासिल करने की कोशिश कर रहा है, खासकर परिसीमन जैसे मामलों में। लोकसभा की बात करें तो, एनडीए के पास अब 318 सीटें हैं, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस (इंडिया) के पास 184 सीटें हैं और अन्यधनिर्दलीय के पास 38 सीटें हैं। तीन सीटें खाली हैं। दो–तिहाई बहुमत के लिए एनडीए को 362 वोटों की जरूरत होगी। इसलिए, हम देखेंगे कि भाजपा आने वाले समय में और भी गंदी राजनीति करेगीकृजैसा कि हमने पहले भी देखा हैकृसिर्फ अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, बिना किसी नैतिकता या उसूलों की परवाह किए। भारत समाचार बंगाल में, राज्य भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने कहा था कि उनकी पार्टी किसी भी बागी टीएमसी नेता को अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेगी। लेकिन अब उनका कहना है कि हालिया शामिल होने की घटना एक श्अपवाद है, न कि तय नीति से कोई विचलन।श यह भाजपा नेताओं के असली रंग को दिखाता है। ऐसी खबरें हैं कि भाजपा और भी राजनीतिक दलों और नेताओं को तोड़ने की कोशिश कर रही है, या कम से कम श्गाजर और छड़ीश (लालच और दबाव) की नीति समेत कई तरीके अपना कर उनका समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रही है, जिसमें लोकतांत्रिक नियमों, नैतिकता और मूल्यों का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है।

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की कैद,27000 रुपए लगा जुर्माना

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम सुरेंद्र प्रताप यादव की अदालत ने 4 वर्ष पूर्व नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को बुधवार को 20 वर्ष के सश्रम करावास एवं 27000 रुपए अर्थ दंड से दंडित किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए शासकीय अधिवक्ता वेद प्रकाश तिवारी ने बताया कि अभियोजन कथानक के अनुसार रामपुर थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने अभियोग पंजीकृत करवाया कि उसकी 15 वर्षीया नाबालिग पुत्री को 28 मई 2022 को स्कूल जा रही थी

रास्ते में रविंद्र पाल पुत्र पन्नालाल पाल उसे बहला फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ 8–9 महीने तक लगातार बलात्कार करता रहा। 7 मार्च 2023 को उसकी पुत्री को एक लड़की पैदा हुई जब यह सूचना देने वह अभियुक्त के यहां गया तो उसके परिजन गाली गलौज करते हुए मारपीट पर उतारू हो गए। पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता वेद प्रकाश तिवारी एवं रमेश चंद्र पाल के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी युवक को दोष सिद्ध पाते हुए उक्त दंड से दंडित किया।

ट्रस्ट ने पाई चंपत-अनिल मिश्रा से मुक्ति, वेबसाइट से हटा विवरण, कृष्ण मोहन होंगे नए महासचिव

लखनऊ, (संवाददाता)। चढ़ावा चोरी के मामले में घिरे रहे चंपत राय और डॉ. अनिल मिश्रा के इस्तीफे मंजूर होने के बाद सोमवार को अब उनकी पूरी डिटेल ट्रस्ट की वेबसाइट से भी हटा दी गई। वेबसाइट पर सिर्फ ट्रस्ट के 12 पदाधिकारियों व सदस्यों का विवरण उपलब्ध है। एक तरह से अब दोनों का कनेक्शन ट्रस्ट से पूरी तरह से कट चुका है। प्रकरण में 26 जून को चंपत राय ने महासचिव व अनिल मिश्रा ने सदस्य के पद से इस्तीफा दिया था। 27 जून को ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने इसकी पुष्टि की थी। छह जुलाई को हुई ट्रस्ट की बैठक में दोनों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए थे। उसके बाद से चंपत व अनिल ने मंदिर आना बंद कर दिया है। लेकिन अब तक वेबसाइट अपडेट नहीं हुई थी। सोमवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की वेबसाइट अपडेट कर दी गई। जिसके बाद इन दोनों के नाम, फोटो व अन्य विवरण हटा दिया गया है। अब सिर्फ उसमें 12 पदाधिकारियों व सदस्यों का ही विवरण मौजूद है। इसमें ट्रस्ट के अध्यक्ष, महंत नृत्य गोपाल दास, अंतरिम महासचिव कृष्णमोहन, कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी व सदस्य पद्मश्री के. परासरण, स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती महाराज, स्वामी विश्वप्रश्नतीर्थ, परमानंद गिरी, दिनेंद्र दास के अलावा चार पदेन सदस्य, नृपेंद्र मिश्रा (निर्माण समिति अध्यक्ष), आईएएस प्रशांत लोखंडे, आईएएस संजय प्रसाद व डीएम अयोध्या शशांक त्रिपाठी शामिल हैं। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में संगठनात्मक बदलाव का दौर जारी है। सूत्रों के अनुसार, डॉ. कृष्ण मोहन 22 जुलाई को ट्रस्ट के महासचिव का पदभार ग्रहण कर सकते हैं। विगत छह जुलाई को हुई ट्रस्ट की बैठक में उन्हें अंतरिम महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत शांता फाउंडेशन ने गोपी घाट पर किया पौधारोपण

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। पर्यावरण संरक्षण और हरित भविष्य के संकल्प के साथ जौनपुर में चल रहे श्एक पेड़ मां के नामश अभियान के तहत मंगलवार को शांता फाउंडेशन ने नगर के गोपी घाट पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान संस्था के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने 10 पौधे रोपित कर उनके संरक्षण का संकल्प लिया। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आह्वान पर पूरे देश में चलाए जा रहे वृहद वृक्षारोपण अभियान का हिस्सा है। इसके तहत धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और सरकारी संस्थाएं बड़े पैमाने पर पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रही हैं। शांता फाउंडेशन के अध्यक्ष ने कहा कि पौधारोपण का उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों को शुद्ध ऑक्सीजन, स्वच्छ वातावरण और हरित पर्यावरण उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि संस्था अब तक हजारों पौधे लगा चुकी है और भविष्य में भी यह अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि केवल पौधे लगाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनकी देखभाल और संरक्षण की जिम्मेदारी भी सभी को निभानी चाहिए। पौधों के बड़े होने से पर्यावरण संतुलित रहेगा और आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण मिल सकेगा। कार्यक्रम में शांता फाउंडेशन की महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष कल्पना गुप्ता, प्रबंधक दीप्ति गुप्ता, उपाध्यक्ष निशांत सिंह, ज्योति श्रीवास्तव, स्मित श्रीवास्तव, संध्या गुप्ता, पूनम विश्वकर्मा, शुभम रामदास सहित संस्था के अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।

स्टेट कैपिटल रीजन में बनाए जाएंगे 50 लाख सस्ते मकान, 2.50 करोड़ की आबादी को आवासीय सुविधा

लखनऊ, (संवाददाता)। नेशनल कैपिटल रीजन (एनसीआर) की तर्ज पर स्टेट कैपिटल रीजन (एससीआर) में जरूरतमंदों के लिए करीब 50 लाख सस्ते मकान बनाए जाएंगे। इससे करीब 2.50 करोड़ की आबादी को आवासीय सुविधा मिलेगी। इसके अलावा सीतापुर में केजीएमयू, एसजीपीजीआई और एम्स की तरह 300 बेड का मल्टी सुपर स्पेशिएलिटी हॉस्पिटल (टेरिटरी मेडिकल फैसिलिटी सेंटर) बनेगा। इससे एससीआर में आने वाले छह जिलों के लोगों को इलाज के लिए एक और बेहतर विकल्प मिलेगा। एससीआर विकसित करने पर करीब पांच लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे। करीब 26 हजार वर्ग किमी के क्षेत्रफल वाले एससीआर में शामिल लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी और रायबरेली के बीच हाई स्पीड कनेक्टिविटी की सुविधा होगी। इसके लिए मिसिंग रोड नेटवर्क को पूरा करने के साथ रैपिड रेल, रिंग रोड व एक्सप्रेसवे का काम कराया जाएगा। एससीआर के लिए जीआईएस आधारित क्षेत्रीय महायोजना तैयार करने का काम भी तेजी से चल रहा है। इसके लिए कंसल्टेंट का चयन हो चुका है और वह विभागों के साथ मिलकर महायोजना को तैयार करने का काम कर रहा है। इस पर करीब 71 करोड़ रुपये खर्च होंगे और एक वर्ष में रीजनल प्लान तैयार होगा। इसके बाद कंपनी अगले पांच वर्ष की परियोजनाओं को चिह्नित करते हुए उनकी डीपीआर तैयार करेगी। इन्हें शुरू भी किया जाएगा। एससीआर में आने वाले जिलों की कुल आबादी अभी करीब तीन करोड़ है, जो वर्ष 2051 तक 30 करोड़ से अधिक पहुंच जाएगी। इसे ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई जा रही हैं। एससीआर की प्रारंभिक रिपोर्ट में लखनऊ में करीब 13 लाख, सीतापुर में 10 लाख, हरदोई में नौ लाख, बाराबंकी में सात लाख, उन्नाव में छह लाख और रायबरेली में पांच लाख मकानों की जरूरत का आकलन है। इन मकानों को बनाने के लिए करीब 70 हजार एकड़ जमीन की जरूरत होगी। एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार का कहना है कि एससीआर के लिए बनाईं योजनाओं का प्रेजेंटेशन शासन में हुआ है। इन्हीं के आधार पर जीआईएस आधारित महायोजना बनाई जा रही है। इसके बाद डीपीआर बनेगी और फिर उसके हिसाब से जमीन पर काम शुरू 6 होगा। इसमें अभी कई साल लग जाएंगे। टेरिटरी मेडिकल फैसिलिटी को जानेंरू यह सबसे उन्नत और विशिष्ट स्तर की चिकित्सा सुविधा है। जब प्राथमिक और द्वितीय स्तर के अस्पताल किसी बीमारी का इलाज नहीं कर पाते तो मरीज को यहीं रेफर किया जाता है। यहां गंभीर और जटिल बीमारियों का इलाज होता है। साथ ही बड़ी सर्जरी की जाती है। यहां पर एमसीएच डिग्री वाले विशेषज्ञ डॉक्टर तैनात होते हैं। आईसीयू, एमआरआई, सीट स्कैन, पेट स्कैन जैसी सुविधाएं मिलती हैं।

ज्यादा वसूली गई जीएसटी घर खरीदारों को मिलेगी वापस

लखनऊ, (संवाददाता)। यूपी रेरा ने बिल्डरों द्वारा आवंटियों से अधिक वसूली गई जीएसटी राशि वापस करने की प्रक्रिया स्पष्ट की है। जीएसटी विभाग की ऑनलाइन व्यवस्था से ऐसे पात्र घर खरीदार, जिनसे किसी प्रमोटर ने निर्धारित दर से अधिक जीएसटी वसूला है, उसका रिफंड प्राप्त कर सकेंगे। यूपी रेरा ने कहा कि प्राधिकरण में पंजीकृत रियल एस्टेट परियोजनाओं में जीएसटी की वसूली केवल केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार की जानी चाहिए। निर्धारित जीएसटी दरों की जानकारी सभी पंजीकृत प्रमोटर्स एवं रियल एस्टेट एजेंट्स को पहले ही उपलब्ध कराई जा चुकी है।

जौनपुर में भारत स्काउट एवं गाइड की प्रधानाचार्यों की कार्यशाला आयोजित, प्रशिक्षण को लेकर दिए गए महत्वपूर्ण निर्देश

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। टीडी इंटर कॉलेज के मार्कंडेय सभागार में बुधवार को भारत स्काउट एवं गाइड उत्तर प्रदेश की जिला संस्था, जौनपुर द्वारा प्रधानाचार्यों की बैठक एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जनपद के माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों, स्काउट–गाइड पदाधिकारियों, प्रशिक्षकों और काउंसलरों ने भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश कुमार यादव ने कहा कि वर्तमान समय में स्काउट एवं गाइड का प्रशिक्षण विद्यार्थियों के नैतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, चारित्रिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि स्काउट–गाइड का उद्देश्य विद्यार्थियों में सेवा, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति की भावना विकसित करना तथा उन्हें जनपद से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए तैयार करना है। उन्होंने सभी प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया कि अपने–अपने विद्यालयों में स्काउट एवं गाइड इकाइयों का पंजीकरण, नवीनीकरण एवं प्रशिक्षण प्रत्येक वर्ष नियमानुसार कराया जाए। साथ ही नवंबर 2025 में आयोजित नेशनल जंबूरी में जौनपुर की प्रदेश में सर्वाधिक भागीदारी रहने पर जिले के सभी स्काउट–गाइड पदाधिकारियों, प्रशिक्षकों एवं काउंसलरों को बधाई भी दी। कार्यशाला के समापन अवसर पर टीडी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य एवं जिला आयुक्त (स्काउट) डॉ. सत्य प्रकाश सिंह ने संस्था की गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए स्काउट एवं गाइड कार्यालय के संचालन के लिए अपनी पुरानी बिल्डिंग के दो कक्ष उपलब्ध कराने की घोषणा की। उन्होंने इसे जिला संस्था की लंबे समय से चली आ रही महत्वपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति बताया। कार्यक्रम में सहायक जिला विद्यालय निरीक्षक विवेक कुमार सिंह, जिला आयुक्त (गाइड) डॉ. चंद्रकला सिंह, सहायक प्रदेश संगठन आयुक्त (वाराणसी मंडल) जय प्रकाश दक्ष, जिला सचिव डॉ. आलोक सिंह, मुख्यालय आयुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह, सह जिला आयुक्त डॉ. रामदत्त सिंह, डॉ. राकेश कुमार यादव, डॉ. आशीष सिंह, डॉ. शैलेंद्र कुमार सिंह, डॉ. राकेश कुमार सिंह, डॉ. रणजीत सिंह सहित जनपद के अधिकांश माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य, स्काउटर, गाइडर, काउंसलर एवं प्रशिक्षक उपस्थित रहे।

संक्षिप्त खबरें

मुख्यमंत्री ने जहां रोपे थे पौधे, वहां भरा पानी

लखनऊ, (संवाददाता)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुकरैल वन क्षेत्र स्थित महर्षि चरक औषधीय वन में पौधरोपण किया था। विश्व पर्यावरण दिवस पर रोपे गए इन पौधों के चारों ओर पानी भर गया है। इस जलभराव के कारण करीब 200 पौधों के सड़ने और गलने का संकट खड़ा हो गया है। स्वास्थ्य, चिकित्सा और आयुर्वेद को ध्यान में रखते हुए इस औषधीय वन में विशेष प्रजाति के पौधे लगाए गए थे। इनमें नीम, आंवला, अर्जुन, बहेड़ा, अशोक, सहजन, कढ़ी पत्ता और बेल सहित अन्य औषधीय पौधे शामिल हैं। करीब एक बीघे में किए गए इस पौधरोपण से पहले जमीन को सही तरीके से समतल नहीं किया गया था। ढलान की वजह से बारिश के पानी की निकासी नहीं हो सकी और वहां जलभराव हो गया है। वन की देखरेख कर रहे कर्मचारी ने बताया कि पानी भरने से पौधों की जड़ें सड़ने लगी हैं। जलभराव के कारण पौधों की जड़ों तक ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, जिससे छोटे पौधे नष्ट हो रहे हैं। हालांकि, सूख चुके पौधों की जगह नए पौधे लगाए जा रहे हैं ताकि औषधीय वन में पौधों की संख्या कम न हो। डीएफओ सितांशु पांडेय के अनुसार, औषधीय वन की नियमित देखरेख की जा रही है। वहां पानी न जमा हो, इसके लिए व्यवस्था की जाएगी।

ब्लूटूथ से नकल करता अभ्यर्थी गिरफ्तार

लखनऊ, (संवाददाता)। मानकनगर स्थित रेलवे इंटर कॉलेज में सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की परीक्षा के दौरान ब्लूटूथ डिवाइस से नकल करता अभ्यर्थी पकड़ा गया। आरोपी ब्रजेश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। केंद्र व्यवस्थापक डॉ. एमके. सिद्दीकी के अनुसार, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) की मुख्य परीक्षा के दौरान जौनपुर के जरासी चंदवक निवासी ब्रजेश यादव के कान में ब्लूटूथ और हाथ में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिली। पूछताछ में उसने बताया कि परीक्षा शुरू होने से पहले उसने बाथरूम में ब्लूटूथ और डिवाइस छिपा दी थी। चेकिंग के बाद वह दोबारा बाथरूम गया और ब्लूटूथ और डिवाइस निकालकर परीक्षा कक्ष में पहुंच गया। इंस्पेक्टर ने बताया कि जांच में सामने आया कि वह केंद्र के बाहर मौजूद अपने सॉल्वर साथी की मदद से प्रश्न पत्र हल कर रहा था।

खेत में मिला किसान का शव, करंट लगने से मौत की आशंका

लखनऊ, (संवाददाता)। गुडंबा के भाखामऊ में रविवार देर शाम किसान फूलचंद (62) का शव खेत में लगे हाईटेंशन तार के पोल के पास पड़ा मिला। परिजनों ने आशंका जताई है कि करंट की चपेट में आने से फूलचंद की मौत हुई है। उनके बेटे शिवकुमार ने बताया कि पिता रविवार शाम किसी काम से पैदल घर से निकले थे। शाम लगभग सात बजे दूसरे गांव के प्रधान वीरेंद्र यादव ने उन्हें फोन कर पिता का शव मिलने की सूचना दी।

गोमती किनारे निर्माण पर रोक, करीब 2500 करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर पड़ेगा असर

लखनऊ, (संवाददाता)। गोमती के दोनों किनारों पर चल रहे कंक्रीटीकरण और निर्माण कार्यों पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सख्त रुख अपनाया है। उसने गंगा संरक्षण नियमों का हवाला देते हुए गोमती के किनारों, नदी तल और सक्रिय बाढ़ क्षेत्र में नियमों के विपरीत किसी भी निर्माण पर रोक लगा दी है। इससे करीब 2500 करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर असर पड़ेगा। पर्यावरण कार्यकर्ता एडवोकेट आलोक सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. अफरोज अहमद की पीठ ने नौ जुलाई को यह अंतरिम आदेश पारित किया। इसके साथ ही एलडीए समेत सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। याचिका में गोमती के किनारे और सक्रिय बाढ़ क्षेत्र में तटबंध, चार लेन सड़क, बहुमंजिला इमारतों समेत विभिन्न निर्माण कार्यों को चुनौती दी गई है। आलोक सिंह ने बताया कि पिपराघाट पुल से शहीद पथ तक गोमती के एक किनारे पर तटबंध बनाया जा रहा है, जबकि शहीद पथ से किसान पथ तक नदी के दोनों किनारों पर तटबंध का काम चल रहा है। पर्यावरणीय मानकों के अनुसार नदी के किनारे से 400 मीटर तक ऐसे निर्माण नहीं होने चाहिए। कई स्थानों पर नदी के किनारे से महज छह से 20 मीटर की दूरी पर तटबंध बनाया जा रहा है। याचिका में कहा गया कि एलडीए, सिंचाई व जल संसाधन विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों की मिलीभगत से निर्माण कराए जा रहे हैं। इससे पहले से प्रदूषण की मार झेल रही गोमती को स्थायी नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ गया है। अधिकरण ने प्रथमदृष्टया मामले को गंभीर माना है। गंगा नदी (संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रबंधन) प्राधिकरण आदेश, 2016 के अनुसार गंगा सिर्फ मुख्य धारा का नाम नहीं है। इसमें उत्तराखंड की प्रमुख नदियों से लेकर प्रयागराज, गंगासागर तक की पूरी गंगा धारा और उसकी सभी सहायक नदियां शामिल हैं। गोमती भी गंगा नदी तंत्र का हिस्सा है। इस कारण गोमती के संरक्षण और उसके बाढ़ क्षेत्र में होने वाले निर्माण पर भी इसी आदेश के प्रावधान लागू होते हैं। इन क्षेत्रों में स्थायी या अस्थायी निर्माण की अनुमति नहीं है। एनजीटी के आदेश के बाद गोमती किनारे चल रहीं निर्माण परियोजनाएं कानूनी जांच के दायरे में आ गई हैं। संबंधित एजेंसियों को साबित करना होगा कि निर्माण के लिए वैधानिक मंजूरियां ली गई हैं और कार्य वर्ष 2016 के नियमों के अनुरूप है। पुल, सड़क और तटबंध जैसी परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की पूर्व स्वीकृति का मुद्दा भी जांच का हिस्सा रहेगा। अब नदी के किनारे चल रहे निर्माण कार्यों की वैधता की जांच एनजीटी की निगरानी में होगी। ग्रीन कॉरिडोर योजना के फेज–3 के तहत पिपराघाट से शहीद पथ तक करीब छह किमी लंबे हिस्से में गोमती के किनारे तटबंध चौड़ा करने, मिट्टी की भराई और चार लेन सड़क का हो रहा है निर्माण। गोमतीनगर एक्सटेंशन स्थित पुलिस हेडक्वार्टर के सामने गोमती नदी फेसिंग की जमीनें बिल्डरों को दे दी गई हैं। यहां बन रही बहुमंजिला इमारत पर भी आदेश का असर पड़ेगा।

लापता युवक का बाराबंकी में मिला था लहूलुहान शव

लखनऊ, (संवाददाता)। सआदतगंज के बीबीगंज चिकमंडी निवासी इंटर के छात्र मोहम्मद सैफ (18) के लापता होने का मामला 28 दिन बाद नया मोड़ ले गया। पुलिस ने परिजनों को बताया कि सैफ की 14 जून की रात बाराबंकी के सफेदाबाद में सड़क हादसे में मौत हो गई थी। पहचान न होने पर पुलिस ने शव का अंतिम संस्कार करा दिया था। अब सैफ के पिता ने उसके दोस्त समेत तीन लोगों के खिलाफ अपहरण और हत्या की एफआईआर दर्ज कराई है। सैफ की मां यास्मीन बानो ने 17 जून को बेटे की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पिता मोहम्मद आसिफ के अनुसार, 14 जून की शाम करीब छह बजे सैफ घर से निकला था। काफी तलाश के बावजूद उसका कोई पता नहीं चला। 28 दिन बाद पुलिस ने जानकारी दी कि डिवाइडर से बाइक टकराने से सैफ की मौत हो गई थी। सोमवार को उन्होंने सैफ के दोस्त अली, लकड़मंडी निवासी सुमित गुप्ता और मरी माता बरौरा निवासी मुस्कान पर आरोप लगाया कि तीनों ने बेटे का अपहरण कर उसकी हत्या की और घटना को सड़क हादसे का रूप दे दिया। इंस्पेक्टर संतोष कुमार आर्य ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर में गंभीर चोट लगने और कोमा में जाने से मौत की पुष्टि हुई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हादसे के समय बाइक अली चला रहा था। यह बाइक उन्नाव से चोरी की गई थी। तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है और उनके आपराधिक इतिहास की भी जांच की जा रही है। जांच में यह भी पता चला है कि आरोपी मुस्कान पर दो माह पहले अपने पूर्व पति पर चाकू से हमला करने का आरोप लग चुका है। परिजनों का कहना है कि हादसे के बाद अली ने घटना की सूचना किसी को नहीं दी।

कैसे भी मंदिर मैनेजमेंट में फिर से घुसना चाहते हैं गोपाल राव, एसआईटी की रिपोर्ट का ले रहे हैं आधार

लखनऊ, (संवाददाता)। मंदिर प्रबंधन में हस्तक्षेप रखने वाले गोपाल राव एसआईटी रिपोर्ट का हवाला देकर सफाई देने में जुटे हैं। वह दोबारा किसी न किसी तरह से मंदिर प्रबंधन से जुड़ना चाहते हैं। इसके लिए संघ के बड़े पदाधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं। ट्रस्ट की बैठक से पहले भी वह कर्नाटक गए थे। तब भी वह पदाधिकारियों से मिले थे, जिसमें उन्होंने अपनी भूमिका सिरे से खारिज कर दी थी। उनको आस है कि वह मंदिर प्रबंधन से फिर से जुड़ सकते हैं। गोपाल राव कर्नाटक में संघ के अहम पदों पर रह चुके हैं। मंदिर निर्माण के समय उन्हें राम मंदिर भेजा गया था। उनको निर्माण सहायक बनाया गया था। साथ ही वह ट्रस्ट की बैठकों में विशिष्ट आमंत्रित सदस्य के तौर पर शामिल होते थे। हालांकि, चंपत राय और अनिल मिश्रा के साथ गोपाल का तीसरे नंबर पर सबसे अधिक दखल रहता था, खासकर मंदिर प्रबंधन से जुड़े निर्णय लेने में। यही वजह है कि जब चोरी की वारदात हुई तो गोपाल पर भी तमाम सवाल उठे, जो अभी भी बने हुए हैं। जब एसआईटी की रिपोर्ट सामने आई तो उसमें ट्रस्ट के सभी कर्मियों व पदाधिकारियों की भूमिका बताई गई। जेल गए आरोपियों की संलिप्तता स्पष्ट की गई और अनिल मिश्रा को जिम्मेदार ठहराया गया। कहीं पर भी रिपोर्ट में गोपाल राव का जिक्र नहीं था। विज्ञापन सूत्र बताते हैं कि गोपाल राव अब यह सफाई देने में लगे हैं कि उनकी किसी भी तरह की भूमिका गणना प्रक्रिया आदि में नहीं रहती थी। इसलिए उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। उन पर लगाए गए सभी आरोप गलत हैं। एसआईटी ने भी कहीं पर उनके बारे में नहीं लिखा है। विश्वसनीय सूत्र बताते हैं कि गोपाल इसलिए संघ को अपनी सफाई दे रहे हैं, जिससे आने वाले समय में किसी न किसी तरह से वह मंदिर प्रबंधन से जुड़े रहें। सूत्रों का कहना है कि ट्रस्ट में किसी पद पर न रहने की वजह से एसआईटी ने उनकी भूमिका का जिक्र नहीं किया है। लेकिन, यह पूरी तरह स्पष्ट है कि कुछ लोगों की भर्ती कराने से लेकर प्रबंधन के हर कार्य में उनका हस्तक्षेप रहता था। इसलिए कहीं न कहीं उनकी जिम्मेदारी तय की गई है। इसलिए उनकी वापसी आसान नहीं होगी या यह कहें कि वापसी की संभावना न के बराबर है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में संगठनात्मक बदलाव का दौर जारी है। सूत्रों के अनुसार, डॉ. कृष्ण मोहन 22 जुलाई को ट्रस्ट के महासचिव का पदभार ग्रहण कर सकते हैं। विगत छह जुलाई को हुई ट्रस्ट की बैठक में

उन्हें अंतरिम महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उसी बैठक में तत्कालीन महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्र के इस्तीफे भी स्वीकार कर लिए गए थे।अब 22 जुलाई को प्रस्तावित श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में ट्रस्ट की नई टीम का ऐलान किया जाएगा। बैठक में डॉ. कृष्ण मोहन के महासचिव पद पर औपचारिक अनुमोदन की पूरी संभावना जताई जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इसके साथ ही ट्रस्ट में रिक्त पड़े तीन अन्य पदों पर भी नए चेहरों की नियुक्ति की तैयारी अंतिम चरण में बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक, नामों पर लगभग सहमति बन चुकी है और अब केवल औपचारिक घोषणा शेष है। इसी क्रम में अयोध्या राजपरिवार के सदस्य यतींद्र मोहन मिश्र को भी ट्रस्ट में सदस्य के रूप में शामिल किए जाने की चर्चा तेज है।

ताजमहल, आगरा किला और सीकरी के 5 किमी दायरे में पेड़ कटाई के नए नियम

आगरा, (संवाददाता)। ताजमहल के बाद आगरा किला और फतेहपुर सीकरी के 5 किमी. दायरे में पेड़ नहीं काटे जा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल इंपावर्ड कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की है, जिसमें किला और फतेहपुर सीकरी में भी पेड़ों की कटाई और छंटाई पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बीते साल एक मई को अपने आदेश में ताजमहल की 5 किमी. हवाई दूरी तक पेड़ों की छंटाई और कटाई पर रोक लगा दी थी। किला और सीकरी के लिए कोर्ट ने सीईसी से रिपोर्ट मांगी थी, जो अब दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट के स्वतरू संज्ञान याचिका 08/2026 में सेंट्रल इंपावर्ड कमेटी के सदस्य सचिव सतीश गरकोटी ने कोर्ट को कई सिफारिशें की हैं। इनमें कहा गया है कि डीएफओ पेड़ों की कटाई और छंटाई की अनुमति तब देंगे, जब गंभीर या तत्काल आवश्यकता हो। तुरंत कटाई न करने पर मानव जीवन की हानि की आशंका हो। डीएफओ और सीईसी अगर अनुमति दे देते हैं तो अनुमति देने के 15 दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट में विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। इसमें छंटाई व कटाई से पहले और बाद की तस्वीरें अपलोड करनी होंगी। सेंट्रल इंपावर्ड कमेटी ने रिपोर्ट में कहा है कि ताज ट्रेपेजियम जोन में केवल ताज नहीं, बल्कि किला और फतेहपुर सीकरी का भी पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक विरासत संरक्षित करनी है। इन स्मारकों के पास अंधाधुंध कटाई से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इससे धूल का स्तर बढ़ सकता है, तो तापमान भी बढ़ने के आसार हैं। एयर क्वालिटी खराब होगी और मिट्टी का कटाव शुरू हो सकता है। केवल कुछ मामलों में, जिनमें सार्वजनिक अवसंरचना परियोजनाओं, सार्वजनिक सुरक्षा, नागरिक सेवाओं के लिए काटने की अनुमति दी जा सकती है।

जमीन की लालच में पत्नी ने प्रेमी संग रची थी पति की हत्या की साजिश

अयोध्या।जमीन अपने नाम कराने की चाहत में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ साजिश कर अपने ही पति की हत्या कर दी।इसका खुलासा बुधवार को एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने अपने कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान किया।बताया कि 12 जुलाई को रुदौली थाना क्षेत्र के कूढ़ा सादात मार्ग के किनारे झाड़ियों में एक अज्ञात शव मिला था।पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने गहन जांच शुरू की।शव की पहचान बाराबंकी निवासी देवेन्द्र कुमार वर्मा (48) के रूप में हुई।बताया कि मृतक की पत्नी शुभांगिनी वर्मा ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से पति की हत्या करवा दी थी। बताया कि मृतक की पत्नी शुभांगिनी वर्मा का पति से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था।इसी

बीच उसका बाराबंकी निवासी विपिन वर्मा से प्रेम संबंध हो गया।दोनों ने मिलकर देवेन्द्र को रास्ते से हटाने की साजिश रची।11 जुलाई को विपिन, देवेन्द्र को अयोध्या घुमाने के बहाने घर से ले गया और सुनसान स्थान पर हथौड़ी से वार कर उसकी हत्या कर दी।बाद में शव को सड़क किनारे झाड़ियों में फेंक दिया गया।पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि पुलिस को इस घटना के खुलासा सीसीटीवी कैमरों, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से हुआ।पुलिस ने आरोपी विपिन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पत्रकार वार्ता में एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी, सीओ रुदौली अरविंद सोनकर, सीओ रंजना, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली रुदौली संजय मौर्य मौजूद रहे।

गेमिंग वेबसाइट के जरिए साइबर ठगी करने वाले दो आरोपियों को मवई पुलिस ने किया गिरफ्तार

अयोध्या। थाना मवई और साइबर क्राइम थाना की संयुक्त टीम ने प्लेयर्स 77.काम नामक गेमिंग व ट्रेडिंग वेबसाइट के माध्यम से साइबर ठगी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया।बुधवार को एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने अपने कार्यालय में इसका खुलासा किया।बताया कि पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से छह मोबाइल फोन, एक टैबलेट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं। साथ ही उनके बैंक खातों में कुल 63 लाख रुपये फ्रीज कराए गए हैं।बताया कि गिरफ्तार गिये आरोपी अकील अहमद उर्फ उर्फी निवासी बसौढ़ी, अयोध्या और अमन खान निवासी उन्नाव,मवई क्षेत्र में कॉल सेंटर संचालित कर लोगों को ऑनलाइन गेम में निवेश का लालच देते थे। गिरफ्तार किए गए आरोपी पहले तो भोले भाले लोगों को दुगनी रकम की लालच देकर कुछ पैसे तो वापस कर देते थे लेकिन जब वही भोले भाले लोग इनकी सेकेंडरी में फंसकर अधिक रकम जमा करते थे तो इस गिरोह में शामिल आरोपी इनका जमा पैसा वापस नहीं करते थे। गेम में पैसा लगाने के बाद रिफंड के नाम पर टैक्स और सर्विस चार्ज मांगकर साइबर ठगी की जाती थी।जांच में आरोपियों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से करीब 11 हजार गेमिंग आईडी–पासवर्ड, लेनदेन का रिकॉर्ड और व्हाट्सएप चौट बरामद हुई हैं।बताया कि पुलिस ने अकील के बैंक ऑफ बड़ौदा खाते में 6 लाख रुपये तथा एक संदिग्ध एचडीएफसी खाते में 57 लाख रुपये फ्रीज कराए हैं। मामले में एक अन्य आरोपी सुफियान फरार है, जिसकी तलाश जारी है।दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना मवई में बीएनएस और आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।पत्रकार वार्ता मे एसएसपी डॉ गौरव ग्रोवर के अलावा एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी, सीओ सदर व साइबर क्राइम प्रतीक कुमार मौजूद रहे।

करंट लगाकर दी यातनाएं, बेरहमी से की हत्या, गंभीर आरोपों के बाद बढ़ाए गए दो और नाम

आगरा, (संवाददाता)। आगरा के ट्रांस यमुना स्थित भगवती बाग में खराद मैकेनिक दिनेश शर्मा की मौत के मामले में दूसरे दिन सोमवार को भी हंगामा हुआ। परिवार के लोगों ने पुलिस पर आरोपी को बचाने का आरोप लगाया। पत्नी और तीसरे बेटे के नाम को भी प्राथमिकी में जोड़ने की मांग की। काफी देर तक तकरार के बाद पुलिस ने मौके पर ही मृतक के बेटे के बयान लिए। इसके बाद प्राथमिकी में दो और नाम बढ़ा दिए। अब पुलिस ने मामले में विधि क राय ले रही है। वहीं, 15 घंटे बाद शव का अंतिम संस्कार किया जा सका। भगवती बाग निवासी दिनेश शर्मा खराद कारखाने में काम करते थे। वह बीसी (लाटरी) भी चलाते थे। रविवार सुबह 9रू30 बजे वो 100 मीटर दूर रहने वाले उदय अग्रवाल के घर गए थे। बेटे

विष्णु ने आरोप लगाया कि उदय पर पिता के पांच लाख रुपये थे। रुपये मांगने पर उसने पिटाई की जिससे पिता की मृत्यु हो गई। घटना के बाद परिजन आक्रोशित हो गए थे। उन्होंने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की थी। सूचना पर पुलिस पहुंची थी। पुलिस ने किसी तरह मामला शांत कराया था। मामले में मृतक के बेटे की तहरीर पर उदय अग्रवाल, उसके बेटे आकाश और लखन के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई। रात 9 बजे शव को पोस्टमार्टम के बाद घर लाया गया मगर परिजन आरोपी को जेल भेजने की मांग पर अड़ गए। उन्होंने अंतिम संस्कार से इंकार कर दिया। तनाव को देखते हुए क्षेत्र में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। सोमवार सुबह भी परिजन अंतिम संस्कार के लिए राजी नहीं हुए। थाने पहुंचे परिजन ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए।

पत्रकार एसोसिएशन का भव्य वार्षिक समारोह, इम्तियाज खान बने अध्यक्ष

ब्यूरो चीफ
आलोक कुमार श्रीवास्तव

सुल्तानपुर। पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की तहसील इकाई बल्दीराय का वार्षिक समारोह मंगलवार को ब्लॉक सभागार में गरिमामय वातावरण में आयोजित किया गया। इस अवसर पर संगठन की नई तहसील कार्यकारिणी की घोषणा की गई, जिसमें इम्तियाज खान को सर्वसम्मति से तहसील अध्यक्ष चुना गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अवधेश शुक्ला ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। मुख्य अतिथि इसौली विधायक मोहम्मद ताहिर खान ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हैं और समाज की समस्याओं को निष्पक्षता से शासन–प्रशासन तक पहुंचाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने जनहित के मुद्दों को विधानसभा में उठाने का भरोसा दिलाते हुए पत्रकारों से निष्पक्ष एवं जिम्मेदार पत्रकारिता करने का आह्वान किया। जिला पंचायत प्रतिनिधि एवं ब्लॉक प्रमुख शिव कुमार सिंह ने कहा कि पत्रकारों को जनप्रतिनिधियों के अच्छे कार्यों के साथ–साथ कमियों को भी बेबाकी से उजागर करना चाहिए, ताकि व्यवस्था में निरंतर सुधार हो सके। समारोह के दौरान संगठन की वार्षिक स्मारिका का विमोचन किया गया तथा पदाधिकारियों और सदस्यों को परिचय–पत्र वितरित किए गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अवधेश शुक्ला ने नई कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए इम्तियाज खान को तहसील अध्यक्ष, प्रेम प्रकाश वर्मा को उपाध्यक्ष, डॉ. धर्मेंद्र सिंह को महामंत्री, मोहम्मद तफसीर अहमद को कोषाध्यक्ष तथा ए.एन. पांडेय एवं सुहेल आलम को संरक्षक नियुक्त किया। वही संगठन के वरिष्ठ सदस्य बब्बन वर्मा, सुधा सिंह,पुष्कर सुल्तानपुरी,अफसर खान,शाहबाज खान,लौलाक खान,तनवीर आलम,आलोक श्रीवास्तव,सहित पत्रकार रंजीत सिंह, सुरेंद्र मिश्रा,नितिन मिश्रा,बाल गोविंद मौर्य, हनुमान तिवारी,ज्ञान पांडेय,शिवम श्रीवास्तव, बलवीर यादव,इस्राइल अहमद की उपस्थिति सराहनीय रही।

सांस्कृतिक सत्र में कवि पुष्कर सुल्तानपुरी और विकास चौरसिया ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं का मन मोह लिया। कार्यक्रम का संचालन कर्म शर्मा ने किया। नवनिर्वाचित तहसील अध्यक्ष इम्तियाज खान ने सभी अतिथियों, पत्रकार साथियों और उपस्थित जनों के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में दिवंगत पत्रकार के.के. तिवारी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दो मिनट का मौन रखकर शोक संवेदना व्यक्त की गई। इस अवसर पर डॉ. अवधेश,ई०आनंद भर्ती, त्रिपाठी, आचार्य सूर्यभान पांडेय, हिन्देश सिंह,डॉ राजेश प्रजापति,एस डी ओ एम पी सिंह, बलबीर यादव, राजधार शुक्ला,पूर्व प्रधान कृष्ण कुमार यादव,अरशद बेग,ई०निहाल अहमद,सहरे आलम,कफील अहमद,जिला पंचायत सदस्य बद्रीनाथ यादव,डॉ शोएब खान, बजरंग सिंह,मुरलीधर वर्मा, ग्राम प्रधान अकबर अली, अब्दुल्ला खान सहित बड़ी संख्या में पत्रकार, जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

महिला थानाध्यक्ष आशा शुक्ला ने छात्राओं को किया जागरूक

अयोध्या। बुधवार को मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला थानाध्यक्ष आशा शुक्ला के नेतृत्व मे महिला उप निरीक्षक श्वेता राठौड़ ने पीआरडी राजकुमारी के साथ अयोध्या रिकाबगंज चौराहे पर अभियान चलाकर छात्राओं को सुरक्षात्मक उपाय बताये।इस मौके पर उन्होंने वहाँ पर मौजूद छात्राओं से अपील किया कि आप सभी घर से निकलते समय हमेशा सतर्कता बरते।इस मौके पर उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के प्रति जागरूक व सुरक्षात्मक उपाय भी बताई।इस मौके पर उन्होंने महिलाओं तथा बालिकाओं को सुरक्षात्मक टिप्स

की भी जानकारी दिया।उन्होंने विधवा केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं जिसमे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन एवं सुकन्या समृद्धि योजना और हेल्पलाइन नंबर के बारे में महिलाओं को जागरूक किया।इसके अलावा उन्होंने उन्हें किसी भी प्रकार की पुलिस सहायता हेतु विमेन पावर लाइन 1090, यूपी 112, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, चाइल्ड लाइन 1098, साइबर अपराध 1930 के बारे में बताया गया।बताया कि यह सभी नंबर आप लोग हमेशा याद रखें। जब भी आपको किसी भी प्रकार की सहायता लेने की जरूरत हो तो आप इस नंबर पर फोन कर सकते हैं।

सांसद–विधायक ने रखी फोर–लेन सड़कों की मांग

उन्नाव, (संवाददाता)। एक्सप्रेसवे के लोकार्पण समारोह में आए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन विभाग के मंत्री नितिन गडकरी से मुख्यमंत्री की मौजूदगी में सांसद साक्षी महाराज और पुरवा विधायक अनिल सिंह ने जिले और विधानसभा क्षेत्र के लिए चार लेन सड़कों की मांग रखी। इस पर गडकरी ने मुख्यमंत्री के माध्यम से मांगपत्र और एनओसी भेजने के लिए कहा। सांसद ने उन्नाव–हरदोई मार्ग को चार लेन हाईवे बनाने की मांग की, वहीं पुरवा विधायक अनिल सिंह ने उन्नाव–पुरवा–मोहनलालगंज मार्ग को चार लेन बनाने की मांग की। इस पर सड़क परिवहन मंत्री ने कहा कि बजट की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मांग पत्र और एनओसी भेजिए, जो भी सड़कें हाईवे चाहिए सब बनाएंगे। पुरवा विधायक ने मुख्यमंत्री से डिफेंस कॉरिडोर स्थापित कराने की भी मांग की। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरेंद्र कुशवाहा को रविवार की रात उनके घर सिंगरोसी में कोतवाली पुलिस

रात में फॉल्ट और दिन में बिजली कटौती ने झेलाया

गोरखपुर, (संवाददाता)। रविवार देर शाम शुरू हुई बारिश के बाद महानगर की बिजली व्यवस्था बेपटरी हो गई। शाहपुर और तारामंडल उपकेंद्र से जुड़े इलाकों में पूरी रात फॉल्ट, लो वोल्टेज और उतार–चढ़ाव की समस्या बनी रही। सोमवार को गोलघर फीडर से जुड़े एक हजार से अधिक घरों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की बिजली घंटों बाधित रही। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी में परेशानी का सामना करना पड़ा। शाहपुर उपकेंद्र से जुड़े करीब 1500 परिवारों की बिजली रविवार रात करीब 10 बजे गुल हो गई। जो आधी रात के बाद बहाल हुई। हालांकि पूरी रात बिजली में अस्थिरता रही।

करंट की चपेट में आने से युवक की मौत परिजनों ने लगाया जबरदस्ती काम कराने का आरोप

ब्यूरो चीफ . सुलतानपुर

सुलतानपुर । तुराबखानी (लाखीपुर) में लाइट का काम करते समय करंट की चपेट में आने से एक 20 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई मृतक की पहचान दुर्गेश पुत्र मुरली निवासी ग्राम कुबेरशाह पट्टी थाना लम्भुआ के रूप में हुई हैं जानकारी के अनुसार दुर्गेश मजदूरी करने तुराबखानी गया था रात करीब 12रू00 बजे काम के दौरान उसे करंट लग गया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई घटना के बाद मोर्चरी हाउस के पास परिजनों का भारी जमावड़ा लगा हुआ हैं मृतक की बहन दीपा और जीजा रिंकू ने आरोप लगाया हैं कि ठेकेदार जबरदस्ती दुर्गेश से लाइट का काम करवाते थे परिवार वालों का रो–रो कर बुरा हाल हैं दुर्गेश की शादी 3 महीने पहले ही हुई थी घर में कोहराम मचा हुआ हैं पुलिस मामले की जांच में जुटी हैं पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा।

तीन दिन की हड़ताल से गल्ला कारोबारियों को नौ करोड़ का नुकसान

बांदा, (संवाददाता)। तीन दिन से चल रही गल्ला मंडी में कारोबारियों की हड़ताल से करीब नौ करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। हड़ताल का जहां सरकारी खजाने पर असर पड़ा वहीं दैनिक मजदूरों के सामने भी रोजी–रोटी का संकट है। व्यापारियों के समर्थन में सोमवार को तिंदवारी और मटौंध गल्ला मंडी में भी कारोबार बंद कर दिया। इसी कड़ी में व्यापारियों ने मंडलायुक्त को मांगों का ज्ञापन भी सौंपा है। मंगलवार को बुंदेलखंड के जिलों से व्यापारी बांदा पहुंचकर प्रदर्शन में शामिल होंगे। बांदा गल्ला व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष विष्णु कुमार गुप्ता ने बताया कि गल्ला मंडी बांदा में करीब 350 कारोबारी हैं।

एक लाख के इनामी मुस्तफिजुल का एसटीएफ ने किया एनकाउंटर

गोरखपुर, (संवाददाता)। गोरखपुर में एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम के साथ सोमवार देर रात हुई मुठभेड़ में एक लाख रुपये का इनामी मुस्तफिजुल रहमान उर्फ बाबू मारा गया। इस दौरान मुख्य आरक्षी महेंद्र सिंह भी गोली लगने से घायल हो गए। उनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस के अनुसार, सोमवार रात करीब 11 बजे रामनगर करजहा से कुशीनगर लेन के पास एसटीएफ और पुलिस की टीम चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान आजमगढ़ के मेहनगर खुन्दनपुर निवासी मुस्तफिजुल का पुलिस से सामना

हो गया। उसने भागने की कोशिश की तो टीम ने उसका पीछा किया। इस पर उसने फायरिंग शुरू कर दी। इसमें मुख्य आरक्षी महेंद्र सिंह घायल हो गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मुस्तफिजुल के भी पैर में गोली लग गई। इसके बाद पुलिस टीम ने उसे दबोच लिया। दोनों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां देर रात मुस्तफिजुल की मौत हो गई। मौके से पुलिस ने 32 बोर की एक पिस्टल, एक बाइक और भारी मात्रा में खोखा और कारतूस बरामद किए। मुस्तफिजुल के खिलाफ कई राज्यों में हत्या, हत्या के प्रयास सहित गंभीर मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। वर्ष 2024 में वह महाराष्ट्र पुलिस की हिरासत से भी फरार होने में कामयाब हो गया था। मुस्तफिजुल पर कई राज्यों में दर्ज हैं गंभीर मुकदमे रामनगर करजहा में सोमवार रात मुठभेड़ में गिरफ्तार आजमगढ़ निवासी मुस्तफिजुल पर कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार मुस्तफिजुल के विरुद्ध सबसे पहला मुकदमा वर्ष 2003 में आजमगढ़ के मेहनगर थाने में चोरी के मामले में दर्ज किया गया था। इसके बाद वर्ष 2008 में हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। वर्ष 2011 में वह एक अन्य हत्या के प्रयास के मामले में नामजद हुआ, जिसके बाद से वह फरार था। वर्ष 2012 में आरोपी के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश का मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले में बाद में न्यायालय के आदेश पर उसके विरुद्ध सीआरपीसी की धारा 82ध्83 के तहत उद्घोषणा एवं संपत्ति कुर्की की कार्रवाई भी की गई। वर्ष 2021 में हत्या के एक मामले में इस पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया। इसी वर्ष उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 174–ए तथा धारा 506 के तहत अलग–अलग मुकदमे भी दर्ज किए गए।

2 साल तक पति ने नहीं बनाए वैवाहिक संबंध, इलाज के नाम पर मांगे 5 लाख रुपये

गोरखपुर, (संवाददाता)। गोरखनाथ क्षेत्र की 30 वर्षीय विवाहिता ने पति और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोप है कि शादी के बाद पति ने करीब दो साल तक वैवाहिक संबंध नहीं बनाए। पति बीमारी और दवा के कोर्स की बात कहकर दूरी बनाए रखता था। इलाज की बात कहने पर मायके से पांच लाख रुपये का दबाव बनाया। विरोध करने पर मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। महिला ने तहरीर में बताया कि पति की समस्या के इलाज के लिए सितंबर 2025 में लखनऊ के मेट्रो हॉस्पिटल लेकर गई थी। डॉक्टर ने जांच के लिए सैंपल मांगा लेकिन प्रयास के बाद भी पति सैंपल नहीं दे पाए। आरोप है कि इसके बाद पति घबराहट की बात कहते हुए अस्पताल से चले गए। आरोप है कि इसके बाद ससुराल पक्ष इलाज के खर्च का हवाला देकर मायके से पांच लाख रुपये की मांग करने लगा। रुपये देने से इन्कार करने पर उसके साथ मारपीट की गई और घर से निकाल दिया गया। आरोप है कि इलाज की बात करने पर ससुराल वाले नाराज हो जाते थे और विरोध करने पर मारपीट करते थे। महिला के अनुसार, उसकी शादी 19 नवंबर 2021 को लखनऊ के महानगर थाना क्षेत्र निवासी युवक से हुई थी। शादी में मायके वालों ने करीब 10 से 15 लाख रुपये खर्च किए थे। आरोप है कि विवाह के बाद से ही ससुराल में उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। पीड़िता ने बताया कि ससुर की पहले ही मौत हो चुकी है। ससुराल में पति के अलावा सास, देवर, ननद और पति के मामा रहते हैं। गोरखनाथ थाना प्रभारी विजय प्रताप सिंह ने बताया कि महिला की तहरीर पर पति, सास, देवर, ननद समेत पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है।

अब विद्यार्थी करेंगे विश्वविद्यालय का मूल्यांकन, देंगे बेहतरी के लिए सुझाव

गोरखपुर, (संवाददाता)। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की शैक्षणिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का मूल्यांकन अब छात्र भी करेंगे। विश्वविद्यालय नए सत्र से पहली बार 'स्टूडेंट फीडबैक सिस्टम' लागू करने जा रहा है। इसके तहत छात्र बताएंगे कि विश्वविद्यालय में क्या बेहतर है और कहां बदलाव की जरूरत है। फीडबैक में छात्र शिक्षकों की अध्यापन गुणवत्ता, परीक्षा व्यवस्था, प्रवेश प्रक्रिया, स्मार्ट क्लास, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं, कैंटीन, पेयजल, स्वच्छता और शौचालय जैसी सुविधाओं पर अपना सुझाव दर्ज कर सकेंगे। फीडबैक केवल औपचारिकता नहीं होगा बल्कि शिकायतों के निस्तारण की व्यवस्था भी की जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन विद्यार्थियों को निर्धारित फीडबैक फॉर्म उपलब्ध कराएगा। इसमें छात्र पढ़ाई से लेकर परिसर की बुनियादी सुविधाओं तक हर पहलू पर सुझाव और शिकायतें दर्ज कर सकेंगे। इन शिकायतों को संबंधित विभागों को भेजा जाएगा और उनके समाधान की निगरानी की जाएगी। फीडबैक प्रक्रिया में शिक्षक की विषय पर पकड़, अध्यापन शैली, विद्यार्थियों से संवाद, समय पर कक्षाएं लेने, डिजिटल तकनीक के उपयोग और पाठ्यक्रम समय पर पूरा कराने जैसे बिंदुओं का भी मूल्यांकन किया जाएगा। अब तक विश्वविद्यालय में शिक्षकों और कर्मचारियों का मूल्यांकन मुख्य रूप से प्रशासनिक स्तर पर होता रहा है। विश्वविद्यालय पहली बार छात्रों को भी गुणवत्ता आकलन की प्रक्रिया का सक्रिय हिस्सा बनाने जा रहा है। इससे प्रशासन को समस्याओं की वास्तविक जानकारी मिलने से सुधारात्मक कदम उठाने में मदद मिलेगी।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।